an>

Title: Need to take stringent action against micro-finance companies fleecing borrowers in rural areas, particularly in Maharashtra.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : निजी साहूकार द्वारा आर्थिक शोषण के खिलाफ बगावत करने के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बहुत दिनों तक ग्रामीण इलाकों में 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में तमाम बैंक पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं, ऐसी लोगों की आम राय बन गयी थी, तब ग्रामीण क्षेत्र के किसान और छोटे-छोटे कारीगरों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उनके सामने निजी साहूकार के चौखट पर दस्तक देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने साहूकारों के चंगुल से आम जनता को छुड़ाने के लिए उनके खिलाफ सख्त नियम और कानून बनाये। राष्ट्रीकृत बैंकों का एक तरफ विस्तार हो रहा था तो दूसरी ओर साहूकारों के खिलाफ सख्त कानून अमल में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन सख्त कानून के डर से गायब हुए निजी साहूकारों ने 'माइक्रो फाइनेंस कंपनियों' के नाम से साहूकारी का नया जाल फिर एक बार ग्रामीण इलाकों में फैलाने में वे कामयाब हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश के बहुत सारे राज्यों में दो-तीन साल के भीतर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के घोटाले सामने आये हैं, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में और इन कंपनियों के बीच संघर्ष चल रहा है। दुर्भाग्यवश हम सब जनप्रतिनिधि भी यह सब चीजें देखते हुए भी इन सब परिस्थितियों की अनदेखी कर रहे हैं। यह बहुत ही खेद का विषय है।

आर्थिक लूट का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर हुआ है, इनके द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लिए गये कर्ज पर करीब 22 से 35 फीसदी तक का ब्याज वसूल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर 6 से 7 महिलाएं अपना एक गुट बनाती हैं और उस गुट को लोन दिया जाता है। इस लोन की वापसी की अवधि प्रतिदिन या प्रतिमास के किस्त के रूप में होती है और यदि यह लोन समय पर भुगतान नहीं किया तो बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। यह सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं पुरुषों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आखिर में इस तरह से ब्याज की दर 42 से 45 प्रतिशत तक वसूली जाती है।

पूरे देश में फैली हुई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जड़ें सरकार ने अगर खुदवा कर नहीं निकाली तो आज किसान द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, इसके बाद ग्रामीण इलाकों में छोटी महिला उद्यमी और लघु उद्योगपतियों के नाम भी आत्महत्याओं की सूची में दुर्भाग्य से देखने पड़ेंगे इसलिए हर एक राज्य के विशेषकर महाराष्ट्र में पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ तत्काल केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी सक्षम एजेंसी की तरफ से जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

14.54 hours